वैश्विक तनाव से निवेशकों में सतर्कता

आईटी शेयरों में गिरावट से सेंसेक्स-निफ्टी सपाट कारोबार

62 अंक पर गिरा सेंसेक्स

1.41 अंक पर लुढ़का निफ्टी

मुंबई, 5 जनवरी. सोमवार को वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव और शेयरों में गिरावट के कारण भारतीय बाजार सपाट कारोबार करते रहे. सेंसेक्स 62 अंक गिरकर 85,699 पर और निफ्टी 26,319 पर स्थिर रहा.निफ्टी एआई में 1.41 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई, जबकि मीडिया, मेटल और पीएसयू सेक्टर में हल्की बढ़त रही.

विशेषज्ञों का कहना है कि वेनेजुएला संकट, रूस-यूक्रेन संघर्ष और ईरानी विरोध प्रदर्शन जैसी घटनाएं निवेशकों की सतर्कता बढ़ा रही हैं, जिससे बाजार पर अस्थायी दबाव बना हुआ है. सोमवार को वैश्विक तनाव और आईटी शेयरों में गिरावट के चलते भारतीय शेयर बाजार सुस्त और सपाट कारोबार में दिखा. सुबह 9.30 बजे तक, सेंसेक्स 62 अंक या 0.07 प्रतिशत गिरकर 85,699 पर और निफ्टी 9 अंक या 0.03 प्रतिशत बढ़कर 26,319 पर था. निफ्टी आईटी में सबसे बड़ी गिरावट 1.41 प्रतिशत दर्ज हुई, जबकि मीडिया, मेटल और पीएसयू सेक्टर क्रमश: 0.84, 0.70 और 0.79 प्रतिशत बढ़त के साथ प्रमुख गेनर्स रहे.

विश्लेषकों ने कहा कि अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ताजा तनाव, रूस-यूक्रेन संघर्ष और ईरानी विरोध प्रदर्शन जैसे वैश्विक घटनाक्रम निवेशकों की सतर्कता बढ़ा रहे हैं. इसके कारण भारतीय कंपनियों की तिमाही कमाई में सुधार के बावजूद बाजार हल्का नेगेटिव रहा. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी मिश्रित रुझान देखने को मिला.

> अमेरिकी बाजार में डॉव 0.66 प्रतिशत ऊपर गया, एस पी 500 में 0.19 प्रतिशत की बढ़त रही और नैस्डैक में 0.03 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई. विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 2 जनवरी को 290 करोड़ रुपये के इक्विटी शेयर खरीदे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 677 करोड़ रुपये का निवेश किया. विशेषज्ञों ने कहा कि आगामी समय में वैश्विक भू-राजनीतिक घटनाओं के गंभीर परिणाम बाजार पर असर डाल सकते हैं, लेकिन वेनेजुएला संकट से भारत के लिए कच्चे तेल पर मध्यम से लंबी अवधि में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है.

सेल ने बनाया दिसंबर की बिक्री का नया रिकॉर्ड

नई दिल्ली, 05 जनवरी. सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात उत्पादक कंपनी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) की बिक्री दिसंबर 2025 में 37 प्रतिशत बढ़कर 21 लाख टन पर पहुंच गयी. महारत्न कंपनी की यह किसी भी दिसंबर महीने में सबसे अधिक बिक्री है. पिछले साल दिसंबर में उसने 15 लाख टन इस्पात की बिक्री की थी. कंपनी की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह प्रदर्शन सेल द्वारा ग्राहकों को समय पर डिलीवरी देने पर फोकस करने की वजह से रहा. कंपनी हाल के दिनों में नये उत्साह के साथ ब्रांडिंग पहलों पर भी जोर दे रही है. दिसंबर महीने के शानदार प्रदर्शन ने सेल को वित्त वर्ष 2025-26 के पहले नौ महीने के दौरान अपनी विकास गति बरकरार रखने में मदद की है.

सोना-चांदी में तेजी, निवेशकों का रुझान बढ़ा

939 रुपए बढ़ा सोने का भाव

2,225 रुपए महंगी हुई चांदी

नई दिल्ली, 5 जनवरी. नए साल की शुरुआत के साथ ही सोने-चांदी ने निवेशकों को चौंका दिया है. 5 जनवरी को दोनों कीमती धातुओं के दामों में तेज उछाल देखने को मिला. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, 24 कैरेट सोना 939 की तेजी के साथ 1.35 लाख प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया, जबकि चांदी 2,225 महंगी होकर 2.37 लाख प्रति किलो पर कारोबार कर रही है.

सोने-चांदी की कीमतों में एक बार फिर मजबूती देखने को मिली है. सोमवार, 5 जनवरी को इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 939 बढ़कर 1,35,721 हो गया. इससे पहले सोना 1,34,782 प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं, एक किलो चांदी की कीमत रुपए 2,225 की तेजी के साथ 2,36,775 पर पहुंच गई, जो पहले 2,34,550 थी. गौरतलब है कि 29 दिसंबर 2025 को सोना 1,38,161 और चांदी 2,43,483 प्रति किलो के ऑल टाइम हाई स्तर पर पहुंच चुकी है. विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा तेजी उस बड़े ट्रेंड का हिस्सा है, जो 2025 से जारी है. आईबीजेए के रेट्स में 3त्न जीएसटी, मेकिंग चार्ज और ज्वेलर्स मार्जिन शामिल नहीं होते, इसलिए अलग-अलग शहरों में सोने-चांदी के दाम अलग दिखाई देते हैं. इन्हीं दरों के आधार पर आरबीआई सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमत तय करता है और कई बैंक गोल्ड लोन की वैल्यू भी इसी से निर्धारित करते हैं.

सीएसआर खर्च बढ़ा सकता कंपनियों का बोझ

लखनऊ, 5 जनवरी. देश में कंपनियों पर कानूनन लागू किया गया सीएसआर (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) खर्च निवेशकों की नजर में जोखिम बढ़ा सकता है. जिसका सीधा असर यह होता है कि कंपनियों को शेयर बाजार से पैसा जुटाने में ज्यादा लागत चुकानी पड़ सकती है.

भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ द्वारा किए गए एक अध्ययन में यह तथ्य सामने आया है. यह अध्ययन खास तौर पर गरीबी उन्मूलन से जुड़े सीएसआर खर्च पर केंद्रित है. शोध में यह देखा गया कि जब कंपनियां मजबूरी में सीएसआर पर खर्च करती हैं, तो निवेशक इसे कंपनी के फायदे के बजाय एक अतिरिक्त बोझ मानते हैं. इस कारण निवेशकों का भरोसा कुछ हद तक कम होता है और वे ज्यादा मुनाफे की मांग करते हैं.

यह शोध अंतरराष्ट्रीय पत्रिका जर्नल ऑफ एकाउंटिंग इन इमर्जिंग इकोनॉमिक्स में प्रकाशित हुआ है. अध्ययन को आईआईएम लखनऊ के प्रोफेसर सेशादेव साहू और उनकी शोध छात्रा डॉ. सुकन्या वाधवा ने मिलकर किया है. शोध के लिए वर्ष 2014 से 2020 के बीच 484 भारतीय कंपनियों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया. इन कंपनियों ने कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गरीबी हटाने से जुड़े सीएसआर कार्यों पर खर्च किया था.

चावल, चीनी, दालों में तेजी ; गेहूं नरम ; खाद्य तेलों में घट-बढ़

नई दिल्ली, 05 जनवरी. घरेलू थोक जिंस बाजारों में सोमवार को चावल के औसत भाव बढ़ गये. चावल के साथ चीनी और दालों में भी तेजी रही जबकि गेहूं में गिरावट का रुख रहा. खाद्य तेलों की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया. औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 116 रुपये बढ़कर 3,847 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी. गेहूं 21 रुपये सस्ता हुआ और 2,850 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बोला गया. आटा 19 रुपये टूट गया. दाल-दलहनों में तेजी रही. तुअर दाल औसतन 215 रुपये प्रति क्विंटल महंगी हुई. चना दाल की कीमत 172 रुपये और मसूर दाल की 142 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी. मूंग दाल 96 रुपये और उड़द दाल 41 रुपये प्रति क्विंटल मजबूत हुई.

सैमसंग का हर प्रोडक्ट होगा स्मार्ट

एआई तकनीक से बनेगा आपका डिजिटल जीवन साथी

टीवी और स्मार्ट होम में यूजर-केंद्रित अनुभव बढ़ेगा

लास वेगास, 5 जनवरी. सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने सीईएस-2026 से पहले घोषणा की कि वह अपने सभी प्रोडक्ट्स में एआई तकनीक का इस्तेमाल करेगा. कंपनी का उद्देश्य है कि लोग अपने रोजमर्रा के कामों में एआई का स्मार्ट साथी महसूस करें. इसके तहत टीवी, स्मार्ट होम उपकरण और हेल्थ ऐप में एआई अनुभव शामिल होंगे.

'विजन एआई कंपेनियन' यूजर की जरूरत और बातचीत को समझेगा, जबकि हेल्थ ऐप नींद, खान-पान और गतिविधियों को ट्रैक कर स्वास्थ्य सुझाव देगा, और घर के उपकरणों को सहज और स्मार्ट बनाएगा. सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने सीईएस 2026 से पहले घोषणा की है कि वह अपने सभी प्रोडक्ट्स और सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) तकनीक का इस्तेमाल करेगा. कंपनी का लक्ष्य है कि वह लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में एक स्मार्ट और भरोसेमंद एआई साथी बन सके, जो उनकी जरूरतों को समझे और मदद करे. सैमसंग के प्रेसिडेंट रोह ताए-मून ने बताया कि नए 'विजन एआई कंपेनियन' प्लेटफॉर्म के जरिए टीवी और स्मार्ट होम उपकरण यूजर-केंद्रित अनुभव देंगे. यह प्लेटफॉर्म यूजर की बातचीत और जरूरतों को समझकर स्मार्ट सुझाव देगा. 2026 में आने वाले नए टीवी में एचडीआर10+ एडवांस्ड तकनीक के साथ बेहतर ब्राइटनेस, रंग और मूवमेंट क्वालिटी मिलेगी. सैमसंग के स्मार्ट होम उपकरण स्क्रीन, कैमरा और आवाज से यूजर की जरूरतें समझेंगे और अलग-अलग उपकरण आपस में जुड़कर सहज काम करेंगे.

पॉलीपैक और वॉल क्लॉक उद्योग में भी अग्रणी

राज्य सरकार की सहायता से उद्योग और रोजगार को बढ़ावा

मोरबी-गुजरात की आर्थिक और वैश्विक पहचान

राजकोट, 5 जनवरी. गुजरात का मोरबी जिला भारत का प्रमुख सिरेमिक केंद्र बन गया है. यहां भारत के कुल सिरेमिक उत्पादन में लगभग 90 फीसदी हिस्सेदारी है और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिरेमिक उत्पादन केंद्र है.

मोरबी में फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और विट्रिफाइड टाइल्स के उत्पादन के साथ-साथ पॉलीपैक और वॉल क्लॉक उद्योग भी विकसित हैं. जिले में 1200 से अधिक इकाइयां हैं, जो करीब 9 लाख लोगों को रोजगार देती हैं. मोरबी ने 'मेड इन इंडिया-मेड इन गुजरात' ब्रांड को वैश्विक पहचान दी है. गुजरात का मोरबी जिला अब भारत की सिरेमिक राजधानी के रूप में जाना जाता है.

वॉल क्लॉक उत्पादन में देश में सबसे अधिक हिस्सेदारी है

वर्ष 2024-25 में मोरबी से लगभग 15,000 करोड़ रुपए का सिरेमिक निर्यात हुआ, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ओमान और श्रीलंका मुख्य देश हैं . मोरबी का पॉलीपैक उद्योग भी तेजी से बढ़ रहा है, जहां 150 इकाइयां सालाना लगभग 5 लाख मीट्रिक टन पीपी वूवन फैब्रिक का उत्पादन करती हैं . इसके अलावा वॉल क्लॉक और गिफ्ट आर्टिकल उद्योग भी जिले में बड़ी संख्या में विकसित हैं . यहां वॉल क्लॉक उत्पादन में देश में सबसे अधिक हिस्सेदारी है और करीब 10-12 हजार लोग इन उद्योगों से जुड़े हुए हैं, जिनमें 60 फीसदी महिलाएं हैं .

मॉयल लिमिटेड ने रचा नया उत्पादन रिकॉर्ड

नई दिल्ली 05 जनवरी. मॉयल लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही और पहले नौ महीनों के लिए अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ उत्पादन आंकड़े दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-दिसंबर) में अब तक का सबसे अच्छा उत्पादन किया है. वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान, मॉयल लिमिटेड ने 4.77 लाख टन मैंगनीज अयस्क का रिकार्ड उत्पादन किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग 3.7 प्रतिशत की वृद्धि है.

यह कंपनी द्वारा अपनी स्थापना के बाद से किसी भी तीसरी तिमाही में हासिल किया गया अब तक का सबसे ज़्यादा उत्पादन है. इस विकास की गति को और मजबूत करते हुए मॉयल लिमिटेड ने अपना अब तक का सबसे अच्छा नौ महीने का 14.21 लाख टन का उत्पादन भी दर्ज किया है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 6.8 प्रतिशत ज़्यादा है. ॅउत्पादन प्रदर्शन में सतत सुधार, केंद्रित खान योजना, परिचालन अनुशासन, उन्नत मशीनीकरण और सभी परिचालन इकाइयों में मॉयल लिमिटेड के कर्मचारियों के समर्पित प्रयासों का परिणाम है.

आईटी कंपनियों के दबाव में लुढ़के शेयर बाजार

मुंबई, 05 जनवरी (वार्ता) घरेलू शेयर बाजारों में सोमवार को शुरुआती कारोबार में आईटी कंपनियों पर दबाव रहा जिससे प्रमुख सूचकांक गिरावट में चले गये. बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 121.96 अंक टूटकर 85,640.05 अंक पर खुला. यह 216.28 अंक नीचे 85,545.73 अंक पर था. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक 5.15 अंक की बढ़त के साथ 26,333.70 अंक पर खुलने के बाद समय 53.70 अंक यानी 0.20 प्रतिशत गिरकर 26,274.85 अंक पर रहा.

उर्वरक उत्पादन में बड़ी छलांग

डीएपी-एनपीकेएस उत्पादन 10 साल में 50% से ज्यादा बढ़ा

मुंबई, 05 जनवरी. रिजर्व बैंक ने सोमवार को खुले बाजार से 50,000 करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां खरीदीं.

केंद्रीय बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के पास नकदी की उपलब्धता बढ़ाने के उपायों के तहत यह खरीद की है. यह चार समान किस्तों में दो लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद के तहत दूसरी किस्त है. रिजर्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि उसने सात तरह की प्रतिभूतियों की खरीद की है जिनकी मियाद साल 2029 से 2054 तक अलग-अलग समय में पूरी हो रही है. इसमें तीन साल, छह साल, आठ साल, नौ साल, 10 साल, 14 साल और 28 साल की प्रतिभूतियां शामिल हैं. इन प्रतिभूतियों पर 7.09 प्रतिशत से 8.30 प्रतिशत ब्याज दर हैं. पहली किस्त में 50 हजार करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियां 29 जनवरी को खरीदी गयी थीं. अगली दो किस्तों के तहत 12 जनवरी और 22 जनवरी को खरीद की जायेगी. दिसंबर में इससे पहले भी दो किस्तों में केंद्रीय बैंक ने एक लाख करोड़ रुपये की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद की थी.

समाचार विशेष

एमवीए को मिला 'स्वाभिमानी' साथ

राजू शेट्टी ने किया समर्थन का ऐलान

मुंबई. महाराष्ट्र के आगामी नगर निकाय चुनावों से पहले राज्य की सियासत में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. पूर्व सांसद राजू शेट्टी के नेतृत्व वाली स्वाभिमानी पार्टी ने आधिकारिक तौर पर महाविकास आघाड़ी (एमवीए) के उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने की घोषणा कर दी है. यह फैसला सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है.

महंगाई और भ्रष्टाचार को बनाया मुख्य मुद्दा- स्वाभिमानी पार्टी के नेता राजू शेट्टी ने विधान परिषद में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल को लिखे एक पत्र में अपने इस निर्णय के पीछे के ठोस कारणों को स्पष्ट किया है. शेट्टी ने कहा कि आज देश और राज्य के लोग बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कुप्रशासन से त्रस्त हैं. उन्होंने सत्तारूढ़ दलों पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि विकास के नाम पर भ्रष्टाचार चरम पर है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर गरीब और आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है.

क्यों दिया एमवीए को समर्थन?- शेट्टी के अनुसार, महाविकास आघाड़ी (कांग्रेस, शिवसेना-क्ष्ल और ह्ष्टक्क-शरद पवार गुट) के उम्मीदवार जनहित के मुद्दों को उठाने और शहरी नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए चुनावी मैदान में हैं.

उन्होंने पत्र में उल्लेख किया कि जनविरोधी नीतियों के कारण वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है. इसलिए महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए विपक्षी एकजुटता जरूरी है. निकाय स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए स्वाभिमानी पार्टी राज्यभर में एमवीए का साथ देगी.

15 जनवरी को होगा शक्ति परीक्षण

महाराष्ट्र के 29 नगर निकायों के लिए होने वाले यह चुनाव राज्य की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करेंगे . मतदान की तारीख 15 जनवरी है और मतगणना 16 जनवरी को होगी. महायुति (भाजपा, राकांपा-अजीत पवार और शिवसेना-शिंदे गुट) और महाविकास आघाड़ी के बीच होने वाले इस कड़े मुकाबले में स्वाभिमानी पार्टी का समर्थन ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में निर्णायक भूमिका निभा सकता है .

कांग्रेस को सरकार में नहीं शामिल करेगी डीएमके

चेन्नई. कांग्रेस पार्टी के नेता पता नहीं किस सोच में हर जगह पहले से बने हुए समीकरण और राजनीतिक संरचना को ध्वस्त करना चाहते हैं. बिहार में उसने ऐसा किया, जिसका नुकसान सभी पार्टियों को हुआ. उसके बाद कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश को लेकर बयानबाजी करने लगे. उधर महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में गठबंधन टूट ही गया. अब तमिलनाडु में कांग्रेस के नेता हाथ आजमा रहे हैं.

कांग्रेस पार्टी का कहना है कि उसे सरकार में शामिल किया जाए. कांग्रेस को सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए क्योंकि उसके नेताओं का कहना है कि कांग्रेस का भी अपना घोषणापत्र है और जनता से किया गया वादा है, जिसे पूरा करने के लिए उसका सरकार में रहना जरूरी है. कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे से पहले इसकी मांग शुरू कर दी है.

कांग्रेस के तमिलनाडु के प्रभारी गिरीश चोडनकर ने कहा है कि अगले चुनाव से पहले डीएमके को ऐलान करना चाहिए कि कांग्रेस सरकार का हिस्सा बनेगी तभी तालमेल की घोषणा होगी. दूसरी ओर डीएमके नेताओं का कहना है कि कांग्रेस को अगर सरकार में शामिल करने का ऐलान किया गया तो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस की दूसरी पार्टियां भी इसकी मांग करेंगी और फिर जो खिचड़ी सरकार बनेगी उसके लिए काम करना मुश्किल हो जाएगी. दोनों तरफ से इस पर जोर आजमाइश चल रही है. इस बीच कांग्रेस के नेता सरकार के कर्ज के आंकड़े निकाल कर स्टालिन सरकार को कठघरे में खड़ा करने लगे हैं. डीएमके और कांग्रेस के इस विवाद पर विपक्षी गठबंधन की भी नजर है. उधर भी अन्ना डीएमके ने पहले ही साफ कर दिया है कि अगर गठबंधन जीतता है तो वह भाजपा को सरकार में शामिल नहीं करेगी.

बिहार में बड़े बदलाव की आहट

राजद-कांग्रेस के रिश्ते में आ रही दरार ; क्या बिखर जाएगा महागठबंधन?

नई दिल्ली. बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की आहट है. हालिया विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के रिश्ते जिस तरह से ठंडे पड़े हैं, उसने महागठबंधन के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि कांग्रेस बिहार में लालू प्रसाद और उनके परिवार-केंद्रित नेतृत्व से अलग होकर अपना राजनीतिक रास्ता तलाश सकती है. हाल के दिनों में दिल्ली में कुछ अहम मुलाकातों और बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के लगातार तल्ख होते बयानों का संकेत साफ है कि दोनों दलों के रिश्ते असहज हो चुके हैं. दिल्ली में लगभग बीस दिन पहले कांग्रेस की रैली से एक दिन पहले भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य और कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की मुलाकात हुई थी. उसके बाद प्रशांत किशोर और प्रियंका की मुलाकात हुई. इसे बिहार में कांग्रेस के संभावित नए राजनीतिक प्रयोग की शुरुआती कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद दीपंकर ने एक वरिष्ठ समाजवादी नेता से भी कांग्रेस के साथ बिहार की नई संभावनाओं को लेकर विचार-विमर्श किया. इससे संकेत मिलता है कि कांग्रेस केवल गठबंधन की मरम्मत नहीं, बल्कि विकल्पों की तलाश में भी जुट गई है. महागठबंधन में यह अहसास तेज है कि लालू की विरासत से किसी भी तरह की नजदीकी नुकसानदेह ही होगी. भाकपा माले ने पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के साथ मिलकर अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन इस बार उसे भी झटका लगा है. माले के भीतर और सहयोगी दलों में इस हार के लिए तेजस्वी यादव की नेतृत्व शैली पर सवाल उठ रहे हैं.

विशेष | कहीं इंडिया ब्लॉक की साख दांव पर-कहीं भाजपा लगाएगी सेंध

असम से केरल तक 5 राज्यों का रण

नई दिल्ली. साल 2026 भारत के लिए पूरी तरह 'चुनावी साल' रहने वाला है. पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी के विधानसभा चुनावों के साथ-साथ 75 राज्यसभा सीटों और यूपी के पंचायत चुनावों पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जो देश की भावी राजनीतिक दिशा तय करेंगे. साल 2025 के विदा होने के साथ ही देश 2026 के चुनावी मोड में दाखिल हो गया है.

इस वर्ष केवल राज्यों की सरकारें ही नहीं चुनी जाएंगी, बल्कि केंद्र की राजनीति का संतुलन भी प्रभावित होगा. अप्रैल से नवंबर 2026 के बीच देश की 75 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश की 10, बिहार की 5, महाराष्ट्र की 7 और राजस्थान-मध्य प्रदेश की 3-3 सीटें शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र में बीएमसी सहित 29 महानगरों के निकाय चुनाव और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव इस साल को बेहद अहम बना देते हैं. पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 2011 से सत्ता पर काबिज हैं. वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है. ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव अपनी सत्ता के बचाव और चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की चुनौती है, वहीं भाजपा यहां हर हाल में जीत के लिए बेताब है. ांग्रेस और वाम दलों के लिए यह चुनाव अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि उनका वोट शेयर लगातार भाजपा और टीएमसी की ओर खिसक रहा है. तमिलनाडु में मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होने की संभावना है,. एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके ने पिछले चुनाव में 133 सीटें जीती थीं, जबकि एआईएडीएमके को 66 सीटें मिली थीं. 10 मई 2026 को कार्यकाल समाप्त होने से पहले राज्य में चुनाव होंगे.

पुडुचेरी और उपचुनावों का गणित

केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी (30 सीटें) में वर्तमान में एआईएनआरसी और भाजपा का गठबंधन सत्ता में है, जिसके मुख्यमंत्री एन. रंगासामी हैं. इसके अलावा, गोवा, कर्नाटक, यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में होने वाले विधानसभा उपचुनाव और यूपी के पंचायत चुनाव (जिसे 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है) भी 2026 की राजनीतिक तपिश को बढ़ाएंगे. कुल मिलाकर, 2026 का चुनावी परिणाम यह तय करेगा कि इंडिया ब्लॉक अपनी एकजुटता बरकरार रख पाता है या भाजपा का विजयी रथ दक्षिण और पूर्व में अपनी गति बढ़ाता है.